

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष
प्यारे लाल – याचिकाकर्ता**

बनाम

पीठासीन अधिकारी, आई.टी.-और-एल. सी

2011 का CWPNo.19834

फरवरी 18,2013

भारत का संविधान, 1950 - कला, 14, 16 और 226 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - Ss.25F, 25G & 2511 - वन विभाग में बेलदार-सह माली के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता- कारण बताओ नोटिस के बिना सेवाएं समाप्त कर दी गईं - उनसे कनिष्ठ सहकर्मों सेवा में बनाए गए - उनकी छंटनी के बाद उनके जैसे कामगारों की नियुक्ति - उनकी छंटनी के बाद उनके जैसे कामगारों की नियुक्ति - डिसइंगेजमेंट की तारीख से पहले 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी की- श्रम न्यायालय ने इस आधार पर राहत देने से इंकार कर दिया कि दिहाड़ी मजदूर पुन अभिग्रहण का हकदार नहीं है- 10,000/- रुपये का पुरस्कार दिया गया। श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 च का उल्लंघन किया गया था, विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गई- निष्कर्षों से बंधा विभाग-मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत नहीं- रिट अनुमत- 12% ब्याज के साथ सेवा की निरंतरता और बकाया मजदूरी के साथ बहाली का आदेश दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष को वन विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गई है कि अधिनियम की धारा 25-एफओएफ के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए समाप्ति की गई थी। इसलिए, वे उन निष्कर्षों से बंधे हैं।

(पैरा 10)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की अब तक पहुंचने के बाद, श्रम न्यायालय ने मुआवजे के रूप में केवल 36,000 रुपये देना उचित समझा। "मेरे विचार से, यह अधिनियम की धारा 25-एफ के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के सामने न्याय का विवेकपूर्ण वितरण नहीं है।

(पैरा 11)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की परिणामस्वरूप, इस याचिका और संबंधित रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित पुरस्कारों को अलग रखा जाता है। याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का आदेश दिया जाता है। बैंक-वेज को संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से देय और देय होने का आदेश दिया जाता है

क्योंकि उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट नहीं है कि मामलों के इस समूह में प्रबंधन को डिमांड नोटिस कब दिए गए थे। इसलिए, संदर्भ की तारीख से बकाया वेतन देना सुरक्षित होगा। बकाया मजदूरी की गणना की जाए और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर संबंधित कामगारों को भुगतान किया जाए, ऐसा न करने पर बकाया मजदूरी पर नियत तारीख से 12% ब्याज लगेगा, अर्थात् भुगतान तक संदर्भ की तारीख।

(पैरा 14)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की वन विभाग छंटनी के समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनिवार्य प्रावधानों और विशेष रूप से उसकी धारा 25-एफ का अनुपालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों की पहचान करने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। किसी के भी आचरण में लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो इस न्यायालय द्वारा आदेशित बैक-वेजरी को जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों (अधिकारियों) से वसूल किया जा सकता है ताकि सरकारी खजाने को अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवकों की शिथिलता के कारण नुकसान न हो। जांच के परिणाम को पूरा होने के बाद इन मामलों के रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही इस आदेश की एक प्रति हरियाणा सरकार के वन विभाग के सचिव को भी भेजी जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। यह इस अदालत को इन और भविष्य में आसान होने में वन विभाग में प्रचलित जंगल के कानून को ढीला करने का सबसे अच्छा संभव तरीका प्रतीत होता है। अब यह पर्याप्त नहीं है कि एक सीमांत दिहाड़ी मजदूर को बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया जाए और उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, विशिष्ट नौकरशाही के साथ उसकी सूक्ष्म आजीविका से वंचित कर दिया जाए, और फिर उसे वर्षों तक अदालत में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, और फिर बिना वापस मजदूरी के बहाली को स्वीकार करने के लिए कहा जाए। यह मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवीयता का एक और भयानक पहलू है। हमें इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

(पैरा 15)

आर.एस. चौहान, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए

दीपक जिंदल, डीएक्यू हरियाणा

न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना

1. सुना।

2. यह आदेश 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 19834, 2011 की सीडब्ल्यूपी

19843, 2011 की सीडब्ल्यूपी 19899 और 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 19912 को सभी चार आसान में शामिल कानून और तथ्य चाप के सामान्य प्रश्नों के रूप में निपटाएगा। सुविधा के लिए, तथ्यों को 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19834 से लिया गया है।

3. याचिकाकर्ता 2007 के संदर्भ संख्या 16 में श्रम न्यायालय के समक्ष एक कामगार था। उन्होंने जुलाई, 1994 से अक्टूबर, 2003 तक हरियाणा के वन विभाग में सरसाना ब्लॉक, हिसार के हांसी रेंज में बक्लदार-सह-माली के रूप में कार्य किया। औद्योगिक विवाद को उठाते हुए दिए गए डिमांड नोटिस में उन्होंने दावा किया कि उनकी सेवाओं को 1.11.2003 को बिना कारण बताओ नोटिस, चार्जशीट या मुआवजे के अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके सहकर्मी जो उनसे जूनियर थे, उन्हें सेवा में बनाए रखा गया था। उनकी सेवाओं में छंटनी के बाद, उनके जैसे श्रमिकों को हांसी रेंज में उसी क्षेत्रीय ब्लॉक में नियुक्त किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 25-ई, 25-जी और 25-11 का कथित उल्लंघन। उनकी बर्खास्तगी एक मौखिक आदेश द्वारा की गई थी। उस समय उन्हें 2500/- रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था। उन्होंने डिसइंगेजमेंट की तारीख से पहले के बारह कैलेंडर महीनों में 240 दिनों की निरंतर सेंडी पूरी की थी। उन्हें बिलों के बदले मजदूरी का भुगतान किया गया था और उनका नाम मस्टर रोल पर था।

4. आक्षेपित पंचाट में श्रम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 25-1 का अनुपालन न करने के तथ्य का सकारात्मक निष्कर्ष दिया है। श्रम न्यायालय ने इस आधार पर बहाली से राहत देने से इनकार कर दिया है कि एक दिहाड़ी मजदूर बहाली का हकदार नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए श्रम न्यायालय ने **कर्नाटक राज्य के सचिव बनाम उमादेवी और अन्य**, **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम** अशोक कुमार और अन्य², महहूब दीपक **बनाम नगर पंचायत, गजरौला**, **मध्य प्रदेश प्रशासन बनाम त्रिभुवन**, **उत्तरांचल को शेष विकास निगम बनाम एमसी जोशी** और **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ललित कुमार केरमा**।

5. श्रम न्यायालय ने आगे कहा कि कामगार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नियमों और सिद्धांतों का पालन किए बिना दैनिक मजदूरी पर काम कर रहा था। उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया गया

¹ CD 2006 RSJ572

² 2008 (4) SCC 261

³ (2008)1 SCC 575

⁴ (2007)9 SCC 748

⁵ (2007) 2 SCC (L&S) 813

⁶ (2007) 1 SCC 575

था। इसलिए, भले ही कामगार ने 240 दिनों की सेवा पूरी कर ली हो, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि सेवा में कोई बहाली या बैक-वेज मंजूर नहीं किया जा सकता था।

6. श्रम न्यायालय ने पाया कि यह जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य **कृषि विपणन बोर्ड और अन्य, दूरसंचार जिला प्रबंधक और अन्य बनाम केशाह देब**⁷ और अधिशासी अभियंता बनाम **ईश्वर सिंह और अन्य**⁸ के माध्यम से हरियाणा राज्य में **निर्धारित कानून को लागू करके उचित और उचित मुआवजे के हकदार का मामला था**

7. परिणामस्वरूप, 9 वर्ष और 3 माह की निर्बाध सेवा के लिए श्रम न्यायालय ने बहाली के बदले मुआवजे के रूप में केवल 36,000/- रुपए देना उचित समझा। इस याचिका में दिनांक 18.06.2010 के विवादित अधिनिर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है।

8. लिखित वक्तव्य में कई गुणा बचाव किए गए हैं जिनमें यह भी शामिल है कि वन विभाग कोई उद्योग नहीं है; कामगार को अपने ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था; कोई सेवा रिकार्ड नहीं रखा गया था, कामगार ने कोटेशन प्रस्तुत किए थे और न्यूनतम दर की पेशकश करने के बाद, उसे कार्य आबंटित किया गया था और सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर बिलों के प्रति भुगतान किया गया था; कामगार का मुख्य कार्य वृक्षारोपण करना था, विशेष रूप से बरसात के मौसम के दौरान और काम मौसमी प्रकृति के होने के कारण, पूरे वर्ष के लिए रोजगार की कोई संभावना नहीं थी; विभाग में न तो कोई जूनियर रखा गया और न ही उसके बाद; वे अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे; **बंगलौर जल आपूर्त और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा**⁹ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को एक बड़ी न्यायपीठ को भेजा गया है, तथापि, कल्पना के किसी भी सीमा से यह नहीं कहा जा सकता है कि वन विभाग एक उद्योग है; दावा विवरण तीन वर्षों के अंतराल के बाद दायर किया गया है जो देर से किया गया है।

9. जुलाई, 1994 से अक्टूबर, 2003 तक रोजगार सिद्ध करने का दायित्व कर्मकार का था। उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था क्योंकि उनके पास हांसी रेंज में किए गए काम के लिए मस्टर रोल और भुगतान बिलों का रिकॉर्ड था।

10. सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए, उन्होंने श्रम न्यायालय के समक्ष

⁷ 2009 (4) RSJ 367

⁸ 2008 (4) SCT 33

⁹ 2008 (3) SCT 788

¹⁰ 1978(2) SCC 213

एक आवेदन दायर किया जिसमें जुलाई, 1994 से अक्टूबर 2003 तक रिकॉर्ड आईसी मस्टर रोल, इश्यू रजिस्टर, कैश-बुक और बिल (7) 2009 (4) आरएसजे 367 (8) 2008 (4) एससीटी 33 (9) 2008 (3) एससीटी 788 (10) 1978 (2) एससीसी 213 से रिकॉर्ड आईसी मस्टर रोल, इश्यू रजिस्टर, कैश-बुक और बिल तलब करने का अनुरोध किया गया

विभाग। श्रम न्यायालय ने प्रबंधन को संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया क्योंकि मूल रिकॉर्ड के संरक्षक होने और उनकी जानकारी के लिए विशेष होने के कारण इस पर जिम्मेदारी स्थानांतरित हो गई थी। उस निर्देश के अनुसरण में, एक रमेश कुमार, वनपाल उपस्थित हुए और कुछ रिकॉर्ड यानी केश बुक और मस्टर रोल इश्यू रजिस्टर लाए, जिसमें वर्ष 2001 और 2002 में कामगार को किए गए भुगतान दिखाए गए थे। उन्होंने गवाही दी कि कामगारों से संबंधित जून, 2000 से जनवरी, 2004 तक के मस्टर रोल भी जारी किए गए थे, लेकिन वह उत्पादन के लिए मूल मस्टर रोल नहीं लाए थे। उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख पर मस्टर रोल की फोटोकॉपी पेश करने का बीड़ा उठाया। आश्वासन दिए जाने के बावजूद मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किए गए। श्रम न्यायालय ने पाया कि प्रबंधन द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत न किए जाने के कारण गैर-उत्पाद के लिए न्यायोचित कारण के अभाव में कामगार को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ऑन ऑफ रिकॉर्ड। इसके सामने, श्रम न्यायालय ने माना कि कामगार की सेवाओं की समाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष के अनुसार कि अधिनियम की धारा 25-एफ के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में समाप्ति को वन विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए, फ्रे उन निष्कर्षों से बंधे हैं।

11. अब तक पहुंचने के बाद, श्रम न्यायालय ने मुआवजे के रूप में केवल 36,000 रुपये देना उचित समझा, मेरे विचार से, अधिनियम की धारा 25-एफ के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के सामने न्याय का विवेकपूर्ण वितरण नहीं है। धारा 25-एफ का पालन न करने का प्रभाव हाल ही में **अनूप शर्मा** बनाम कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग नंबर 1, पानीपत¹¹, **देविंदर सिंह बनाम नगर परिषद, सनौर, (2011 की सिविल अपील संख्या 3190** 11.4.2011 को निर्णीत) और हरजिंदर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य भंडारण निगम लिमिटेड¹² में **सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा तय किया गया है।**

12. हरजिंदर सिंह (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है:- '30. हाल ही में, सामाजिक कल्याण विधानों की व्याख्या से जुड़े मामलों से निपटने में अदालतों के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव आया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के आकर्षक मंत्र न्यायिक प्रक्रिया का कारण बनते जा रहे हैं और एक धारणा बनाई गई है कि संवैधानिक न्यायालय अब औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। वर्तमान जैसे बड़ी संख्या में मामलों में, कामगारों की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को राहत से वंचित कर दिया गया है,

¹¹ 2010 (3) SCC 497

¹² 2010 (3) SCC 192

जिन्हें तीन दशकों में इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र में बाइडेन और साइड-लेन बनाकर अवैध रूप से सेवा से हटा दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा उठाई गई स्टॉक दलील यह है कि कामगार/कर्मचारी का प्रारंभिक रोजगार/नियुक्ति किसी या अन्य क़ानून के विपरीत थी या कामगार की बहाली से प्रतिष्ठान के वित्तीय स्वास्थ्य पर असहनीय बोझ पड़ेगा। अदालतों ने गलत कर्ता की जवाबदेही की परवाह किए बिना इस तरह की दलील को आसानी से स्वीकार कर लिया है और अप्रत्यक्ष रूप से छोटे लाभार्थी या गलत को दंडित किया है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वह वर्षों से रोजगार में जारी रह सकता है और उसके द्वारा अर्जित सूक्ष्म मजदूरी उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत हो सकती है।

इक्तीस. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका से वंचित है, तो वह अपने सभी मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित है और/या उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता का लक्ष्य है, संविधान में निहित स्वतंत्रताएं भ्रामक हैं। इसलिए, न्यायालयों का दृष्टिकोण संवैधानिक दर्शन के अनुरूप होना चाहिए, जिसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक अभिन्न अंग हैं और नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत दिखावटी और असमर्थनीय आधारों- सार्वजनिक या निजी- को स्वीकार करके कामगार को देय न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। "

13. प्रतिवादी-विभाग द्वारा दायर लिखित बयान में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा मांगे गए मानकों को नहीं मापा गया है। इसलिए, हरजिंदर सिंह (सुप्रा) में निर्धारित कानून के अनुपात को देखते हुए, इस मुद्दे को पहली बार रिट कार्यवाही में नहीं उठाया जा सकता है।

14. नतीजतन, इस याचिका और संबंधित रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई। आक्षेपित पुरस्कारों को अलग रखा गया। याचिकाकर्ताओं ने सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का आदेश दिया। रैक-मजदूरी चाप को संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से देय और देय होने का आदेश दिया गया है क्योंकि उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट नहीं है कि इस समूह में मामलों के लिए प्रबंधन को मांग कब तामील की गई। इसलिए, संदर्भ की तारीख से बकाया वेतन देना सुरक्षित होगा। बकाया मजदूरी की गणना की जाए और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर संबंधित कामगारों को भुगतान किया जाए, ऐसा न करने पर देय तिथि अर्थात् संदर्भ की तारीख से भुगतान तक 12% ब्याज देय होगा।

15. हालांकि, प्रतिवादी-विभाग एक जांच करने और गलती करने वाले अधिकारियों पर देयता तय करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो ऐसा करने का वचन देने के बाद श्रम न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहे। चारों मामलों में प्रबंधन गवाह के रूप में पेश हुए वनपाल रमेश कुमार के आचरण की जांच सरकार के स्तर पर की जा सकती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और विशेष रूप से धारा 25-1 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों की पहचान करने के बाद वन विभाग भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। छंटनी के समय इसके बारे में। यदि किसी का आचरण लापरवाही या अभाव में पाया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा आदेशित बैक-वेजरी को जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारी (अधिकारियों) से वसूल किया जा सकता है ताकि सरकारी खजाने को अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवकों की ढिलाई के कारण नुकसान न हो। जांच के परिणाम को पूरा होने के बाद इन मामलों के रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही इस आदेश की एक प्रति हरियाणा सरकार के वन विभाग के सचिव को भी भेजी जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। यह इस अदालत को इन और भविष्य में आसान बनाने के लिए वन विभाग में जंगल के कानून को प्रचलित होने से रोकने का सबसे अच्छा संभव तरीका प्रतीत होता है। मैं ऐसा हाल ही में इस न्यायालय के रोस्टर में आने वाले प्रतिवादी विभाग को शामिल करते हुए इस तरह के कई सुगमताओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के बाद कहता हूँ, जहां कानून का उल्लंघन बढ़ा है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-च, 25-जी और 25-11 में अंतर्निहित अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायों की घोर अवहेलना करता है। अब यह पर्याप्त नहीं है कि एक सीमांत दिहाड़ी मजदूर को बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया जाए और उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, विशिष्ट नौकरशाही के साथ उसकी सूक्ष्म आजीविका से वंचित कर दिया जाए, और फिर उसे वर्षों तक अदालत में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, और फिर बिना वापस मजदूरी के बहाली को स्वीकार करने के लिए कहा जाए। यह मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवीयता का एक और भयानक पहलू है। हमें इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

16. पीठ ने कहा, "चारों याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

. एल.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए

इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।